Publication	Hindustan
Edition	Delhi, Ghaziabad, Gurgaon, Noida, Faridabad, Meerut, Meerut Janpat
Language/Frequency	Hindi/Daily
Page No	09
Date	25th January 2019

हिन्दुस्तान

मेरठ से दिल्ली के बीच रैपिड रेल के सबंध में नीति आयोग की रिपोर्ट, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में आएगी कमी

रैपिड रेल शुरू होने के बाद हाईवे पर हादसे कम होंगे

मेरठ | मुख्य संवाददाता

दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल प्रोजेक्ट के शुरू होने से मेरठ और गाजियाबाद के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक रैपिड रेल इन दो जिलों में हाईवे से करीब एक लाख वाहन कम कर देगी। इन दो जिलों में इस वजह से सड़क दुर्घटनाओं में 63 फीसदी तक कमी आएगी। एनसीआर में तीन प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भी प्रतिवर्ष 800 टन कमी आएगी।

नीति आयोग ने हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को मेरठ-दिल्ली रैपिड रेल प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। रिपोर्ट में आयोग ने बस रैपिड ट्रांजिट (बीआरटी), मेट्रो रेल के विस्तारीकरण और रैपिड रेल के फायदे गिनाए हैं। रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि अगले एक दशक में दिल्ली सबसे अधिक आबादी वाला शहर होगा। शहरीकरण से एनसीआर में भीड़ अनियंत्रित हो जाएगी। दिल्ली सरकार द्वारा केंद्रीय मंत्रालय को इस प्रोजेक्ट में आने वाले 31 हजार 92 करोड़ रुपये के लागत में अपनी हिस्सेदारी के 1138 करोड़ रुपये देने में असमर्थता जताने से 82 किलोमीटर लंबी यह आरआरटीएस कॉरिडोर योजना अटक गई है।

केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी बाकी

अभी इस प्रोजेक्ट को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिलनी बाकी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2024 में रैपिड रेल में औसतन दस लाख यात्री रोजाना सफर करेंगे। रैपिड रेल से ट्रैफिक जाम में भी 58 फीसदी कमी आएगी। हर साल निजी वाहनों के सड़कों पर कम आने से औसतन 13 हजार 671 करोड़ रुपये की बचत होगी। मेरठ से दिल्ली के बीच इस कोरिडोर की लंबाई 82 किलोमीटर होगी और यह सफर महज 55 मिनट में तय हो जाएगा।

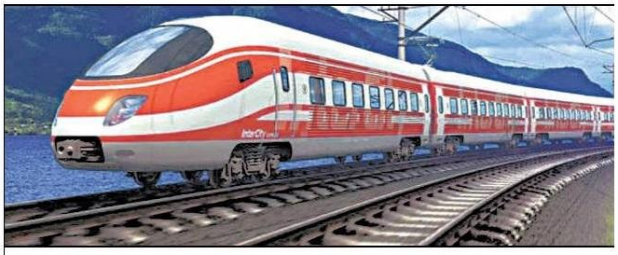

दिल्ली सरकार को कोर्ट का निर्देश

रैपिड रेल की औसत रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। मेरठ-दिल्ली रैपिड रेल प्रोजेक्ट को दिल्ली सरकार ने अभी एनओसी नहीं दी है। दिल्ली राज्य सरकार का तर्क है कि रैपिड रेल के लिए उनके पास 1200 करोड़ रुपये की राशि नहीं है। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक फरवरी तक दिल्ली सरकार को इस संबंध में जवाब दाखिल करने की तारीख देते हुए कहा कि रैपिड रेल जनहित में है और इसमें बहाने नहीं बनाए जाने चाहिए।

पब्लिक ट्रांसपोर्ट शेयर 63 प्रतिशत होगा

रैपिड रेल चलने के बाद एनसीआर में सार्वजनिक परिवहन का शेयर 37 से बढ़कर 63 फीसदी हो जाएगा। एनसीआरटीसी के प्लान के अनुसार साल 2024 में मेरठ से दिल्ली, दिल्ली से अलवर और दिल्ली से पानीपत के बीच रैपिड रेल के कोरिडोर चालू हो जाएंगे।

40 फीसदी प्रदूषण दोपहिया वाहनों से

राज्य और केंद्र सरकार लोगों को सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। दिल्ली में 10 मिलियन से ज्यादा वाहन हैं। कुल वाहन प्रदूषण में, 40 प्रतिशत से 45 प्रतिशत दोपहिया वाहनों से होता है और चार-पहिया से 30 से 35 प्रतिशत तक होता है।